Appointment to the Post of CMD in the SECL

1949. SHRI AJIT P.K. JOGI:
SHRI PRITHIBI MAJHI:

Will the Minister of ENERGY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1962 given in the Rajya Sabha on the 28th November, 1988 and state:

(a) whether it is a fact that another criminal case relating to award of work of coal transportation in Northern Coalfields has since been registered by CBI against the same officer;

(b) whether the officer is still being considered for appointment as CMD of the South Eastern Coalfields Limited; and

(c) what further action has been taken to appoint a suitable person as CMD of this Company?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF COAL IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI C.K. JAFFAR SHARIEF): (a) It is a fact that on request from the CBI, the Coal India Limited forwarded certain papers to the CBI in January this year relating to award of work of coal transportation in Northe Coalfields. Whether the CBI has registered any case on the basis of papers forwarded to them is being ascertained.

(b) No Officer can be appointed to a Scheduled post unless he is cleared from the vigilance angle.

(c) A fresh panel of names has been obtained from the PESB on 5.1.1989. Necessary formalities are being completed to appoint a person from this panel as CMD of the South Eastern Coalfields Limited.

राजस्थान के गांवों का विद्युतीकरण

1950. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया:** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सौर ऊर्जा की मदद से राजस्थान में कितने गांवों का विद्युताकरण किए जाने का विचार है; और

(ख) इन गांवों के लिए सौर ऊर्जा से संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु क्या प्रबन्ध किए गए है?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) प्रारंभिक विद्युतीकरण के एक उपाय के रूप में राजस्थान के 480 गावों में सौर प्रकाशवाल्टीय सड़क बत्ती प्रणालियां लगायी जा चुकी हैं। सातवीं योजना के दौरान लगभग 200 से अधिक गावों में सौर सड़क बत्ती लगाये जाने का अनुमान है। राजस्थान के विभिन्न गांवो मे सामुदायिक केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, शिक्षा केन्द्रों में बत्तियों को ज़लाने के लिए सौर विद्युत पैको की स्थापना भी की गई है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक टेलीविजन देखने के लिए विभिन्न स्थानों पर 52 सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत चालित टेलीविजन सेट लगाए गए हैं।

(ख) अपारपरिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग की वित्तीय सहायता के साथ अनुरक्षण सहित सौर ऊर्जा स्थापना से सम्बन्धित कार्य के निराक्षण का भार मुख्य रूप स राज्य नोडल एजेंसी, नामतः राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी को सौंपा गया है। अन्य प्रबन्धो मे जहा कहीं भी सम्भव है स्थानीय पचायतो को यह प्रबन्ध सौंपना तथा स्थानीय पंचायतों द्वारा बताए गए व्यक्तियो को प्रशिक्षण देना शामिल है।

रसोई गैस के डबल बाटल कनेक्शनों के बारे मे अभिलेखों का रखा जाना

1951 **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के विपणन प्रभाग द्वारा रसोई गैस के डबल बाटल कनेक्शन जारी करने सबंधी कोई अभिलेख नहीं रखे जाते,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इस सम्बन्ध में उक्त निगम को उपयुक्त निदेश जारी करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) से (ग) जी, नहीं। कारपोरेशन द्वारा डबल बाटलिंग कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को जारी किए गए सब्सक्रिप्शन वाउचरों के रूप में रिकार्ड रखे जाते हैं। एल पी जी वितरकों को यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे उन उपभोक्ताओं के उपभोक्ता विवरण कार्ड रखें जिन्हें अतिरिक्त सिलिंडर दिये गये हैं।

राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया राशि

1952. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया**: क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस समय कितने-कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर राज्य बिजली बोर्डों पर विभिन्न संस्थाओं की भारी राशि बकाया है तथा वे घाटे में चल रहे हैं;

(ग) किन-किन राज्य बिजली बोर्डों ने गत तीन वर्षों के दौरान बिजली की दरें बढ़ायी हैं और प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी वृद्धि की गई;

(घ) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड में कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, और

(ङ) किन-किन राज्यों के बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे है, उनमें घाटा होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड से उत्पादित बिजली का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ख) जी, हां।

(ग) बिहार राज्य बिजली बोर्ड को छोड़कर शेष सभी राज्य बिजली बोर्डों ने 1985-88 के दौरान अपनी बिजली की दरें बढ़ाई हैं। चूंकि, बढ़ोतरी की मात्रा भिन्न-भिन्न श्रेणियों और भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है और यह खपत के स्तर पर भी निर्भर करती है इसलिए बढ़ौतरी का परिमाण नहीं बताया जा सकता।

(घ) प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा (संलग्न विवरण-II) में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ङ) 31-3-1988 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित राज्य बिजली बोर्डों को घाटा हुआ है:—

बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय (दस राज्य)।

राज्य बिजली बोर्डों के घाटे में चलने के अनेकानेक कारण हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं:— कृषि क्षेत्र के एवं दूसरे प्रकार के उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली प्रदान करना, राज्य बिजली बोर्डों की खराब वित्तीय स्थिति, देयताओं की समय पर वसूली न होना, विवादास्पद बिजली के बिलों पर मुकदमेबाजी होना, आपूर्ति की गई एवं प्राप्त हुई ऊर्जा तथा ऊर्जा विक्रय की दरों पर सहमति का अभाव, कम उत्पादन, उच्च पारेषण एवं वितरण हानियां आदि। राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन को सुधारने के लिए किए गए महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख संलग्न विवरण-III में किया गया है।